



Drishti IAS



करेंट अफेयर्स

हरियाणा

नवंबर

2022

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009

Inquiry (English): 8010440440, Inquiry (Hindi): 8750187501

Email: help@groupdrishti.in

अनुक्रम

हरियाणा

3

- मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में सीएम डैशबोर्ड और 'सीएम उपहार' पोर्टल किया लॉन्च 3
- हरियाणा में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर 3
- हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के बाद चौथा पुलिस कमिश्नरेट होगा सोनीपत 4
- हरियाणा को मिला इंडिया एग्रीबिज़नेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड 4
- चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नए नाम की नोटिफिकेशन जारी 5
- कैशलेस योजना में कवर होंगे हरियाणा के 6.51 लाख कर्मी 6
- हरियाणा करेगा अपने टैक्स सिस्टम में बदलाव 6
- हरियाणा को मिला 'सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022' 7
- हरियाणा संस्कृत अकादमी ने की वर्ष 2021 के लिये साहित्यकार सम्मानों की घोषणा 7
- राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पंचकूला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र सहित 5 जिले पर्यटन हब में शामिल 8
- गुरुग्राम जिले में पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिये जीडब्ल्यूएस चैनल की बढ़ाई जाएगी क्षमता 9
- कुश्ती प्रशिक्षक सहित हरियाणा के तीन लोगों को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 10
- मानेसर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का होगा शुभारंभ 11
- हरियाणा के साइबर पुलिस स्टेशन में अब टेक्नोक्रेटस को रखा जाएगा 12
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पहली बार यूएनएफसीसीसी- सीओपी में की भागीदारी 12
- इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 हुई अधिसूचित 13
- हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी 'केंद्रीय गृह मंत्री पदक' से सम्मानित 14
- हरियाणा में बनेगा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 14
- प्रदेश भर में स्थापित होंगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 14
- साइबर सिटी गुरुग्राम की अब होगी अपनी मेट्रो ट्रेन 15
- संस्कृत साहित्यकारों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी 15
- हरियाणा ने सुशासन पुरस्कार योजना के शुरू होने की अधिसूचना जारी की 16
- 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ 17
- झज्जर जिला के बाढ़सा में 50 एकड़ में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस 17
- जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कवरेज में अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद अग्रणी घोषित 18
- प्रदेश में 'चिरायु हरियाणा' योजना का शुभारंभ 19
- श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को 'होली कॉम्प्लेक्स' बनाया जाएगा 19
- प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा हरियाणा 20
- राष्ट्रपति ने भगवान श्रीकृष्ण की चौदह विद्याएँ व चौसठ कलाओं पर आधारित सर्वांग-चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन 21
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा को दी 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात 21
- राष्ट्रपति ने किया गीता शिल्प कला उद्यान का उद्घाटन 22

नोट :

हरियाणा

मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में सीएम डैशबोर्ड और 'सीएम उपहार' पोर्टल किया लॉन्च

चर्चा में क्यों ?

31 अक्टूबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में सीएम डैशबोर्ड और 'सीएम उपहार' पोर्टल लॉन्च किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम डैशबोर्ड पोर्टल से सभी विभागों की वास्तविक विश्लेषण समीक्षा की जा सकेगी तथा सभी मुख्य योजनाओं पर उच्चस्तरीय निर्णयों की जानकारी सीएम डैशबोर्ड पर उपलब्ध करवाई जाएगी। इस पोर्टल का गुड गवर्नेंस में भी काफी लाभ होगा।
- इस डैशबोर्ड पर सभी विभागों की कार्यप्रणाली और योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री के लिये सभी बड़े व छोटे स्तरों पर उपलब्ध होगी तथा इस पर कार्यप्रणाली की ट्रैकिंग की जा सकेगी और रिपोर्टों का विश्लेषण करना आसान होगा और इसके द्वारा पुराने और नए डाटा की तुलना की जा सकेगी, जिससे डाटा के आधार पर पूर्व सूचना मिलना संभव होगा।
- उल्लेखनीय है कि यह डैशबोर्ड अत्याधुनिक बिज़नेस इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के साथ इन हाउस विकसित किया गया है।
- इसके अलावा 'सीएम उपहार' पोर्टल के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्राप्त सभी बहुमूल्य भेंटों को पूरे पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन नीलाम किया जाएगा और इस पोर्टल पर देश का कोई भी नागरिक 'उपहार' के लिये बोली लगा सकता है तथा सबसे ऊँची बोली लगाने वाले को विजेता घोषित कर वह उपहार उसे प्रदान कर दिया जाएगा।
- इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज के कल्याण हेतु यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। पोर्टल के माध्यम से उपहारों की नीलामी से प्राप्त धनराशि को मुख्यमंत्री राहत कोष के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के कल्याण में लगाया जाएगा।

हरियाणा में सबसे अधिक बेरोज़गारी दर

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी (सीएमआईई) की तरफ से जारी किये गए आँकड़ों के मुताबिक बेरोज़गारी दर के मामले में हरियाणा देश में प्रथम स्थान पर है।

प्रमुख बिंदु

- सीएमआईई के अनुसार देश में ग्रामीण इलाकों में शहरी इलाकों के मुकाबले बेरोज़गारी दर बढ़ी हुई है। अक्टूबर माह में देश में बेरोज़गारी दर बढ़कर 77 फीसदी पर पहुँच गई। इसमें से शहरी इलाकों में बेरोज़गारी 7.21 और ग्रामीण इलाकों में यह 8.4 फीसदी रही।
- देश के नौ राज्यों में राष्ट्रीय औसत के मुकाबले ज्यादा बेरोज़गारी रही। झारखंड, बिहार और हरियाणा में यह दहाई अंकों में है। 25 में से छह राज्यों में यह दोहरे अंकों में है।
- पिछले छह माह में देश में बेमौसम बारिश, वैश्विक राजनीतिक हालात और ब्याज दरें बढ़ने से उत्पादन में गिरावट आदि बेरोज़गारी के प्रमुख कारण हैं।
- अक्टूबर में बेरोज़गारी दर बिहार, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा रही है।

- हरियाणा में 8 बेरोजगारी दर है तो वहीं राजस्थान में 30.7, जम्मू-कश्मीर में 22.4, झारखंड में 16.5 और बिहार में 14.5 फीसदी है।
- सीएमआईई की तरफ से जारी किये गए आँकड़ों के मुताबिक बेरोजगारी दर के मामले में उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड में हालात बेहतर हैं। उत्तर प्रदेश में यह 2, दिल्ली में 6.7 और उत्तराखंड में 3.4 फीसदी है।
- वहीं सबसे कम बेरोजगारी दर 8 फीसदी के साथ मध्य प्रदेश और 0.9 फीसदी के साथ छत्तीसगढ़ निचले पायदान पर हैं।

हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के बाद चौथा पुलिस कमिश्नरेट होगा सोनीपत

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2022 को हरियाणा में गृह मंत्रालय की ओर से सोनीपत ज़िले को पुलिस कमिश्नरेट बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के बाद सोनीपत ज़िला गुरुग्राम, फरीदाबाद और पंचकूला के बाद राज्य का चौथा पुलिस कमिश्नरेट बन जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- सोनीपत ज़िले के पुलिस कमिश्नरेट बन जाने से यहाँ आईजी रैंक के अधिकारी पुलिस कमिश्नर होंगे और तीन पुलिस जोन बनाए जाएंगे।
- गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव में सोनीपत ज़िले में सभी 15 थानों को तीन जोन में समायोजित किया गया है और जीटी रोड के सभी थानों-गन्नौर, बड़ी, मुरथल, राई, बहालगढ़ और कुंडली पूर्वी पुलिस जोन में शामिल होंगे, जबकि पश्चिमी जोन में थाना सिटी सोनीपत, सदर सोनीपत, सिविल लाइन, सेक्टर-27 और थाना खरखौदा शामिल होंगे। इसके अलावा गोहाना पुलिस जोन में थाना मोहाना, सिटी गोहाना, सदर गोहाना और थाना बरोदा को शामिल किया गया है।
- इन तीनों जोनों का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक रैंक के अधिकारी करेंगे। पुलिस कमिश्नरेट बनाने के निर्णय से ज़िले की सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता होगी।
- उल्लेखनीय है कि हाल ही में सोनीपत ज़िले में मारुति की नई फैक्ट्री का शिलान्यास और रेलवे के कोच नवीनीकरण फैक्ट्री शुरू हुई है।

हरियाणा को मिला इंडिया एग्रीबिज़नेस बेस्ट स्टेट का अवार्ड

चर्चा में क्यों ?

3 नवंबर, 2022 को हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा जारी इंडिया एग्रीबिज़नेस अवार्ड-2022 में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पुरस्कार मिला है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा को यह पुरस्कार राज्य में कृषि अनुकूल नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढाँचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिये मिला है।
- नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति ने कृषि और बागवानी के क्षेत्र में बेहतर तकनीकों, उन्नत विधियों का कार्यान्वयन करने के लिये हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना है।
- हरियाणा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल 9 नवंबर को राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली में हरियाणा की ओर से इस पुरस्कार को ग्रहण करेंगे।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 वर्षों से कृषि, बागवानी क्रांति से नील क्रांति की ओर अग्रसर हरियाणा अब एग्री बिज़नेस में भी आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री के किसानों को जागरूक करने के प्रयासों के फलस्वरूप प्रदेश के किसानों ने बड़ी संख्या में फसल विविधीकरण को अपनाया है। इससे न केवल उनकी आय में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि रोजगार के अन्य अवसर भी खुले हैं।
- भारतीय कृषि को उत्पादन केंद्रित से बाज़ार संचालित व्यवस्था में बदलने की यात्रा में हरियाणा ने मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। हरियाणा सरकार द्वारा कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सुधार के मद्देनजर सिंचाई के लिये पानी का उचित उपयोग, कम पानी की खपत वाली फसलों का विविधीकरण और किसानों की आय बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाओं को लागू करने सहित अनेक कदम उठाए गए हैं।

- वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा कृषि व्यवसाय को बढ़ावा देने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके लिये कृषि क्षेत्र की कंपनियों, किसान उत्पादक संगठनों को चिह्नित किया गया है, ताकि किसानों को संगठित कर सामूहिक रूप से उनके उत्पादन और विपणन की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्य में निवेश, प्रौद्योगिकी और नए उपकरण उपलब्ध करवा कर कृषि एवं बागवानी लागत को कम करने पर भी विशेष बल दिया जा रहा है।
- हरियाणा सरकार एफपीओ के गठन और उन्हें सशक्त करने पर विशेष ध्यान दे रही है तथा अब तक राज्य में लगभग 700 एफपीओ का गठन किया गया है। सरकार द्वारा बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिये इन एफपीओ के साथ काम करने हेतु राज्य में कृषि क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया जा रहा है।
- वर्ष 2021-22 के दौरान, एफपीओ उत्पादों के व्यापार और विपणन के लिये 22 कृषि क्षेत्र की कंपनियों ने बाय बैंक मैनेजिमेंट के साथ 22 एफपीओ के साथ 34 समझौता ज्ञापन किये हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान बागवानी उत्पादों के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर करने के लिये 12 और एफपीओ तथा 15 कंपनियाँ आगे आई हैं।
- राज्य सरकार एफपीओ को उनके हैंडहोल्डिंग के लिये प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। कृषि व्यवसाय के लिये सरकार ने एफपीओ हेतु 'फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम' नामक एक विशेष योजना शुरू की है। इस कार्यक्रम के तहत बागवानी समूहों में एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिये एफपीओ को 70-90 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जाती है। अब तक 30 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किये जा चुके हैं। कृषि विभाग द्वारा कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने को भी प्राथमिकता दी जा रही है।
- एफपीओ को बढ़ावा देने के लिये हरियाणा सरकार 'एफपीओ नीति 2022' लेकर आई है। इस नीति के तहत, विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ संपर्क करने और पंजीकरण, रेटिंग/ग्रेडिंग, निगरानी, विपणन जैसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिये एसएफएसी-हरियाणा राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।
- इस नीति के माध्यम से बागवानी और कृषि के क्लस्टर गठन सहित एफपीओ को सुदृढ़ करना, एफपीओ के सुचारु कामकाज, बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और एकीकरण बिंदुओं पर सॉर्टिंग/ग्रेडिंग के बाद उपज का प्रत्यक्ष विपणन/व्यापार भी सुनिश्चित किया जाएगा।

चंडीगढ़ एयरपोर्ट के नए नाम की नोटिफिकेशन जारी

चर्चा में क्यों ?

4 नवंबर, 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा हरियाणा के चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट नोटिफाई कर दिया गया और तत्कालप्रभाव से यह नाम लागू कर दिया गया।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि 28 सितंबर, 2022 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम 'शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट' किये जाने को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था।
- शहीद भगत सिंह के 115वें जन्मदिवस के मौके पर मोहाली जिले में आयोजित कार्यक्रम में यह नामकरण हुआ था।
- इसी कार्यक्रम के दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से चंडीगढ़ एयरपोर्ट से ज्यादा इंटरनेशनल फ्लाइट्स शुरू किये जाने की भी मांग की थी।
- चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट किये जाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रेडियो ब्रॉडकास्ट 'मन की बात' में बीते 25 सितंबर को की थी।
- इससे पूर्व पंजाब के मुख्यमंत्री और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला की 20 अगस्त 2022 को मीटिंग हुई थी, जिसमें शहीद भगत सिंह के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने पर सहमति बनी थी।
- हालाँकि, इससे पहले हरियाणा ने सिफारिश की थी कि एयरपोर्ट के नाम में पंचकूला का नाम भी शामिल किया जाए, क्योंकि इस एयरपोर्ट के निर्माण में हरियाणा का भी बराबर का हिस्सा रहा है।

कैशलेस योजना में कवर होंगे हरियाणा के 6.51 लाख कर्मों

चर्चा में क्यों ?

7 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि सरकार राज्य में कैशलेस योजना स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने जा रही है जिसके तहत छह लाख 51 हजार से अधिक कर्मचारी, पेंशनभोगी और उनके आश्रितों समेत अन्य श्रेणियों के लोग कवर होंगे।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के अंतर्गत श्रेणी-1 के तहत हरियाणा के सरकारी व निगम कर्मचारियों के तीन लाख 43 हजार 746 परिवार, पेंशनर्स के तीन लाख पाँच हजार परिवारों को यह लाभ मिलेगा।
- श्रेणी-2 में मान्यताप्राप्त पत्रकारों के 1200 परिवार, आजाद हिंद फौज के सैनिकों के 424 परिवार, आपातकाल के दौरान जेल में बंद रहे व्यक्तियों के 555 परिवार, हिन्दी आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के 186 परिवार तथा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जेल में बंद व्यक्तियों के 614 परिवार शामिल किये जाएंगे।
- मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि सूची में शामिल निजी अस्पतालों की भौगोलिक दृष्टि से मैपिंग की जाए तथा योजना के लिये अधिकारियों व कर्मचारी संघों से भी सुझाव लेकर मसौदा तैयार किया जाए।
- उन्होंने बताया कि इस योजना के लिये गैर-सूचीबद्ध अस्पतालों में आपातकालीन स्थितियों में उपचार की अनुमति वर्तमान अभ्यास के अनुसार ही दी जाएगी। 'प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना' के तहत राज्य की राजधानियों, मेट्रो शहरों के पैनेल में शामिल अस्पतालों को भी हरियाणा सरकार की बीमा कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किया जा सकता है।
- विदित है कि पैन इंडिया के पैनेल पर वर्तमान में हरियाणा, ट्राईसिटी, एनसीआर में सूचीबद्ध सभी पैनेल अस्पतालों में सेवाएँ उपलब्ध हैं।
- मुख्य सचिव ने कैशलेस योजना के इस संबंध में अधिकारियों को बीमा योजना का आरएफपी (रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट) भी जल्द तैयार करने का निर्देश दिया है।
- उल्लेखनीय है कि रिक्वेस्ट फॉर प्रोजेक्ट (RFP) एक खरीद प्रक्रिया में एक प्रारंभिक चरण में जारी किया जाता है, जहाँ आपूर्तिकर्ताओं के लिये एक विशिष्ट वस्तु या सेवा पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अक्सर बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक निमंत्रण प्रस्तुत किया जाता है।

हरियाणा करेगा अपने टैक्स सिस्टम में बदलाव

चर्चा में क्यों ?

8 नवंबर, 2022 को हरियाणा के उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य में टैक्स सिस्टम बदलने की तैयारी चल रही है और टैक्स में यह बदलाव मॉड्यूल-1 से मॉड्यूल-2 में किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- उप-मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि टैक्स सिस्टम में समय के साथ यह बदलाव बहुत जरूरी है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से भारत 'एक टैक्स-एक राष्ट्र' के सिस्टम में लीड करेगा तथा आने वाले सालों में भारत में कई नए करदाता जुड़ेंगे और लोगों की टैक्स देने की क्षमता भी बढ़ेगी।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा टैक्स सिस्टम में मॉड्यूल-1 से मॉड्यूल-2 की ओर परिवर्तन कर रहा है, जबकि यह परिवर्तन आसान नहीं है, लेकिन हरियाणा ने साल 2003 में वैट टैक्स प्रणाली को लागू करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी। उसके बाद अन्य राज्यों ने वैट टैक्स प्रणाली को अपनाना शुरू किया था।
- उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा एक उत्पादक राज्य है, जिसकी जनसंख्या 3 करोड़ से कम है और गोवा व दिल्ली को छोड़कर छोटे राज्यों में प्रति व्यक्ति रिसीवर गुड्स में हरियाणा सबसे आगे है, और यहाँ वर्तमान में टैक्स 26 हजार रुपए प्रति व्यक्ति है।
- उन्होंने बताया कि ब्रिटिश हाई कमीशन के सहयोग से यूनाइटेड किंगडम के अधिकारी हरियाणा के 200 से अधिक अधिकारियों को टैक्स प्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दे रहे हैं। यह राज्य का वार्षिक कार्यक्रम है और देश का तेजी से विकास करने के लिये यह जरूरी है।

हरियाणा को मिला 'सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022'

चर्चा में क्यों ?

10 नवंबर, 2022 को भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद द्वारा नई दिल्ली में इंडिया एग्रीबिजनेस अवार्ड-2022 के तहत कृषि क्षेत्र में नीतियों, कार्यक्रमों, उत्पादन, इनपुट, प्रौद्योगिकियों, विपणन, मूल्यवर्धन, बुनियादी ढाँचे और निर्यात के क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदानकर्ताओं को प्रस्तुत करने के लिये हरियाणा को 'बेहतर राज्य'की क्षेणी में पुरस्कृत किया गया।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल ने बताया कि हरियाणा राष्ट्रीय खाद्यान्न पूल में सबसे बड़ा योगदान देने वाले राज्यों में से एक है। राज्य ने बागवानी और कृषि-व्यवसाय को बढ़ावा देने की दिशा में विविधीकरण के लिये कई नीतिगत पहलें की हैं तथा लगभग 400 बागवानी फसल समूहों की मैपिंग की है और 700 किसान उत्पादक संगठनों का गठन किया है।
- क्लस्टरों में बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को मजबूत करने के लिये, हरियाणा ने एक महत्वाकांक्षी योजना 'फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीसीडीपी)' शुरू की है, जिसमें एफपीओ के माध्यम से एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने के लिये 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अब तक 30 एकीकृत पैक हाउस स्थापित किये जा चुके हैं और चालू वित्त वर्ष के अंत तक ऐसे कुल 100 एकीकृत पैक हाउस स्थापित करने का लक्ष्य है।
- कृषि मंत्री ने बताया कि किसानों और कृषि उत्पादों के लिये अंतिम मूल्य श्रृंखला सुनिश्चित करने हेतु कुल 37 कृषि क्षेत्र की कंपनियों ने कृषि-व्यवसाय गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये बाय बैंक तंत्र के साथ एफपीओ उत्पादों के व्यापार और विपणन हेतु 34 एफपीओ के साथ 54 समझौता ज्ञापन निष्पादित किये हैं।
- उन्होंने बताया कि हरियाणा 'भावांतर भरपाई योजना (बीबीवाई)' के माध्यम से मूल्य संरक्षण में अग्रणी रहा है और बागवानी फसलों के लिये 24 करोड़ (पिछले तीन वर्षों में) तथा बाजरा लगभग 750 करोड़ रुपए के साथ प्रोत्साहित किया गया। इसमें वर्ष 2021-22 में 437 करोड़ रुपए से 41 लाख किसानों को कवर किया गया, जबकि वर्ष 2022-23 में लगभग 310 करोड़ रुपए से लगभग 2.25 लाख किसानों को कवर किया गया।
- हरियाणा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन में भी अग्रणी है और इसने राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से 11 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किये हैं। राज्य में राष्ट्रीय कौशल मिशन के तहत साप्ताहिक, मासिक और वार्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से 2500 से अधिक किसानों और उद्यमियों को कुशल बनाने के लिये एक प्रीमियम बागवानी प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है।
- कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि हरियाणा के गन्ना में एशिया की सबसे बड़ी हार्टिकल्चर मार्केट बनने जा रही है। इसके बनने से हरियाणा के किसानों के साथ-साथ पूरे देश के किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इस मार्केट के बनने से कृषि से संबंधित लोगों के लिये उनको एक ही जगह पर सभी चीजें उपलब्ध होंगी, जैसे- सब्जियाँ, फल, फूल, मछली व ड्राई फ्रूट्स आदि। यह मार्केट पेरिस और स्पेन की मार्केट से भी बेहतर बनाई जाएगी।

हरियाणा संस्कृत अकादमी ने की वर्ष 2021 के लिये साहित्यकार सम्मानों की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

9 नवंबर, 2022 को हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि राज्य की संस्कृत अकादमी ने वर्ष 2021 के लिये साहित्यकार सम्मानों की घोषणा कर दी है।

प्रमुख बिंदु

डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान के लिये डॉ. देवी सहाय पांडेय (अयोध्या) को तथा हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिये प्रो. कमला भारद्वाज को चुना गया है।

- वर्ष 2021 के लिये महर्षि वाल्मीकि सम्मान पुरस्कार हेतु करनाल के डॉ.सत्यपाल शर्मा, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान पुरस्कार के लिये पंचकूला के सर्वेश्वर प्रसाद सेमवाल को, महर्षि वेदव्यास सम्मान पुरस्कार हेतु कुरुक्षेत्र के प्रो.अरुणा शर्मा को तथा महर्षि विश्वामित्र सम्मान पुरस्कार के लिये अंबाला के डॉ. चंद्र कुमार झा को चुना गया है।
- महाकवि बाणभट्ट सम्मान के लिये फरीदाबाद के डॉ.गीता आर्या को, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान हेतु पंचकूला के आचार्य स्वामी प्रसाद मिश्र को चुना गया है। इनके अलावा विद्या मार्तण्ड पं. सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान के लिये करनाल की अंजू बाला का चयन किया गया है।
- विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान पुरस्कार कैथल के राजेश नैन को उनकी संस्कृत क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिये प्रदान किया जाएगा। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान वर्ष 2021 के लिये गुरु रविदास संस्कृत महाविद्यालय (गुरुकुल पोहडका) सिरसा का चयन किया गया है।
- डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि इससे पहले अकादमी द्वारा वर्ष 2017 से 2020 तक के पुरस्कारों के लिये चयनित साहित्यकारों को सम्मानित किया जा चुका है तथा शीघ्र ही इन चयनित साहित्यकारों को समारोह आयोजित कर सम्मान प्रदान किये जाएंगे।
- ज्ञातव्य है कि संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान और हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान के लिये साहित्यकार को दो लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति-पत्र प्रदान किया जाता है। इसी तरह महर्षि वाल्मीकि सम्मान, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान, महर्षि वेदव्यास सम्मान, महर्षि विश्वामित्र सम्मान के लिये डेढ़ लाख रुपए प्रदान किये जाते हैं।
- इनके अलावा, महाकवि बाणभट्ट सम्मान, गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, विद्या मार्तण्ड पंडित सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान, स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान और विशिष्ट संस्कृत सेवा सम्मान के लिये एक लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है।

राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पंचकूला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र सहित 5 जिले पर्यटन हब में शामिल

चर्चा में क्यों ?

10 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन-0 योजना के अंतर्गत पर्यटन आधारभूत संरचना के विकास के लिये आयोजित प्रथम राज्य संचालन कमेटी की बैठक में बताया कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये पंचकूला, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद व कुरुक्षेत्र सहित 5 जिलों को पर्यटन हब में शामिल किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि स्वदेश दर्शन-2.0 योजना पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये बेहतर कारगर योजना है तथा इस पर अधिक ध्यान देकर कार्य किया जाना चाहिये, ताकि राज्य में पर्यटन को विकसित करके रोजगार के अवसर भी बढ़ाए जा सकें।
- उन्होंने बताया कि पंचकूला जिले में पर्यटन के लिये संरचनात्मक ढाँचा तैयार करने हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। पंचकूला में मोरनी हिल्स, यादविन्द्रा गार्डन, कौशलया डैम, नाडा साहिब जैसे 55 पर्यटन स्थल हैं।
- महेंद्रगढ़ व फरीदाबाद जिले को भी स्वदेश दर्शन-2.0 योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को पर्यटन मंत्रालय को भेजा जाएगा, ताकि इन जिलों में भी पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। महेंद्रगढ़ में माधोगढ़ का किला, बीरबल का छत्ता, जलमहल, ढोसी पर्वत जैसे अनेक प्राचीन स्मारक स्थल हैं, जिनको पर्यटन के लिये विकसित किया जा रहा है।
- उन्होंने बताया कि फरीदाबाद में ऐतिहासिक सूरजकुंड, दमदमा लेक, अरावली गोल्फ क्लब, सोहना का झरना आदि 17 पर्यटन स्थल हैं तथा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार सूरजकुंड में आधुनिक स्तर का विशेष पर्यटन खंड बनाने पर भी कार्य किया जाएगा, ताकि यह पर्यटकों के लिये और अधिक आकर्षण का केंद्र बन सके।
- ज्ञातव्य है कि यमुनानगर में आदिबद्री, लोहागढ़, हथनीकुंड बैराज, कलेसर नेशनल पार्क, चन्हेटी पिल्लर आदि कई पर्यटक स्थल हैं।

- मुख्य सचिव ने बताया कि स्वदेश दर्शन योजना 0 के तहत पर्यटन एवं संबद्ध बुनियादी ढाँचा, पर्यटन सेवाएँ, मानव एवं पूंजी विकास, स्थल प्रबंधन एवं प्रोत्साहन आदि पर कार्य किया जाना है। इनके अलावा सांस्कृतिक एवं हेरिटेज पर्यटन, साहसिक गतिविधियाँ, ग्रामीण एवं वेलनेस पर्यटन जैसी सुविधाओं और सेवाओं पर भी कार्य किया जाएगा। इसके लिये बैठकें, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी स्थल तथा पर्यटन प्रोत्साहनों को भी बढ़ावा देने के लिये स्थानों का चयन किया जाएगा।
- स्वदेश दर्शन 1.0 योजना के तहत पर्यावरण पर्यटन, वन्य जीव, बुद्धिष्ठ, अध्यात्मिक, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र, तीर्थकर आदि स्थलों का चयन किया गया। इस योजना में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में कृष्णा सर्किट परियोजना को शामिल कर 97.34 करोड़ रुपए की लागत से टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।
- इनमें बहुउद्देशीय पर्यटन सूचना केंद्र, सरोवर की रेलिंग, अभिमन्यु घाट, लाईट एंड साउंड शो जैसी 5 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है, जिसे नवंबर माह में पूरा कर संचालित किया जाएगा तथा कुरुक्षेत्र के थानेसर शेख चिल्ली महल को भी इस योजना में शामिल कर विकसित किया जाएगा।

गुरुग्राम ज़िले में पानी की उपलब्धता में वृद्धि के लिये जीडब्ल्यूएस चैनल की बढ़ाई जाएगी क्षमता

चर्चा में क्यों ?

12 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हुई सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की बैठक में बताया कि राज्य के गुरुग्राम ज़िले में जल आपूर्ति में वृद्धि के लिये गुड़गाँव वाटर सप्लाई चैनल (जीडब्ल्यूएस) की क्षमता में वृद्धि की जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि वर्तमान में गुरुग्राम में वाटर सप्लाई चैनल क्षमता 175 क्यूसेक है, जिसे वर्ष 2030 की जनसंख्या के अनुसार 1000 क्यूसेक बढ़ाया जाएगा। इसके लिये चैनल की मरम्मत और रिमॉडलिंग पर लगभग 1600 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- बैठक में बताया गया कि गुड़गाँव वाटर सप्लाई चैनल की लंबाई 69 किलोमीटर है, जो काकरोई हेड से दिल्ली ब्रांच के आरडी नंबर-227800 से निकलती है और बसई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर खत्म होती है।
- इस चैनल का निर्माण वर्ष 1995 में किया गया था, जिसकी क्षमता 175 क्यूसेक थी। इस चैनल से बहादुरगढ़, गुरुग्राम और जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, एचएसआईआईडीसी एवं वन विभाग के 28 वाटर वर्क्स की पानी की जरूरतें पूरी होती हैं। 27 सालों से लगातार पानी के प्रवाह के कारण चैनल की लाइनिंग खराब हो गई है। कुछ-कुछ जगह चैनल में दरारें भी आ चुकी हैं और गाद भरने की वजह से पानी की क्षमता में कमी आई है तथा इस चैनल की क्षमता 100 क्यूसेक तक पहुँच चुकी है, जिसे मरम्मत की सख्त आवश्यकता है।
- बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों द्वारा भी पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिये इस चैनल से पानी लिया जाता है। इससे यह स्पष्ट देखा जा सकता है कि वर्ष 2040 तक गुरुग्राम शहर व कस्बों में पीने के पानी की आवश्यकता लगभग 475 क्यूसेक तक पहुँच जाएगी। इस मांग को पूरा करने और पानी की बर्बादी से बचाने के लिये क्यूसेक क्षमता बढ़ाने के साथ ही जीडब्ल्यूएस चैनल की रिमॉडलिंग का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है।
- वर्तमान में 1050 क्यूसेक पानी दिल्ली को, 400 क्यूसेक पानी गुरुग्राम को दिया जा रहा है तथा शेष पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किया जा रहा है। इन चैनलों की मरम्मत, रिमॉडलिंग होने से कुल क्षमता 2300 क्यूसेक हो जाएगी, जो वर्ष 2030 तक पानी की उपलब्धता को पूरा कर सकेगी।
- बैठक में बताया गया कि वर्ष 2030 तक हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, एचएसआईआईडीसी, वन विभाग इत्यादि की पानी की जरूरतों के हिसाब से 1068 क्यूसेक की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार, वर्ष 2040 तक 1269 क्यूसेक तथा वर्ष 2050 तक 1504 क्यूसेक पानी की आवश्यकता होगी। इसके लिये दिल्ली ब्रांच की भी पुनः डिजाइन और रिमॉडलिंग की जरूरत पड़ेगी।
- पानी की आपूर्ति के संबंध में बैठक में बताया गया कि यमुना नदी पर रेणुका, किशाऊ और लखवाड़ बांध बनाए जाने प्रस्तावित हैं, जिनका कार्य 2031 तक पूरा होना संभावित है। इन बांधों के बनने से हरियाणा को अपने हिस्से का 1150 क्यूसेक पानी मिलेगा।

- मुख्यमंत्री ने बताया कि पानी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिये आगामी वर्षों में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉलोनियों, एचएसआईआईडीसी द्वारा विकसित इंडस्ट्रियल एस्टेट और निजी डेवलपर द्वारा विकसित कॉलोनियों में भी उपचारित अपशिष्ट जल नीति को पूरी तरह से लागू करना होगा, जिसके तहत डबल पाईपलाइन साफ पानी के लिये अलग और उपचारित पानी के लिये अलग लाईन बिछाना तथा माइक्रो एसटीपी स्थापित करने पर जोर देना होगा और इसके अलावा बारिश के पानी को एकत्र करने की प्रणाली को भी लागू करने पर बल देना होगा।
- मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि गंगा नदी के पानी को हरियाणा में लाने की दिशा में कदम उठाने चाहिये, जिसके लिये गंगा-यमुना लिंक नहर बनाने हेतु जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र लिखा जाए। इस लिंक नहर के बनने से हरियाणा को पानी की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।
- उन्होंने फरीदाबाद महानगरीय प्राधिकरण के अधिकारियों को भी निर्देश देते हुए कहा कि फरीदाबाद में भी पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिये रैनीवेल परियोजना के माध्यम से जल संचयन पर जोर दिया जाए। इसके अलावा, एक एक्सपर्ट कमेटी का भी गठन किया जाए, जो यमुना में अंडरग्राउंड प्लो से संबंधित अध्ययन करेगी और इसके अलावा यह भी आकलन करेगी कि दक्षिण हरियाणा में पानी की कितनी जरूरत है और वर्तमान में कितनी आपूर्ति हो रही है।

कुश्ती प्रशिक्षक सहित हरियाणा के तीन लोगों को मिलेगा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

14 नवंबर, 2022 को युवा कार्य और खेल मंत्रालय ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की घोषणा की। खेल-कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिये 25 खिलाड़ी 2022 के अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करेंगे, जिनमें हरियाणा के सोनीपत के दो खिलाड़ी सीमा अंतिल व पहलवान सरिता मोर शामिल हैं। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक राज सिंह छिक्कारा को द्रोणाचार्य अवार्ड (लाइफटाइम कैटेगरी) के लिये नामित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- पुरस्कार विजेता 30 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति भवन में एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में भारत की राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करेंगे।
- देश के प्रतिष्ठित खेल सम्मान अर्जुन अवार्ड के लिये नामित देश की सबसे अनुभवी एथलीट डिस्कस थ्रोअर सीमा अंतिल पूनिया राष्ट्रमंडल खेलों में पदकों की हैट्रिक जमाने का कारनामा कर चुकी हैं। यह कारनामा उन्होंने वर्ष 2006, 2010 व 2014 में किया था। यही नहीं वह वर्ष 2004, 2012, 2016 व 2022 में भी ओलंपिक कोटा हासिल कर चुकी हैं।
- सीमा अंतिल का जन्म सोनीपत के गाँव खेवड़ा में हुआ था। परिवार में खेलों का माहौल शुरू से था। खेलों के इसी माहौल के बीच सीमा ने डिस्कस थ्रो करना शुरू किया।
- 2016 के रियो ओलंपिक के लिये सीमा ने 62 मीटर डिस्कस थ्रो कर ओलंपिक में जगह बनाई थी। यह उनका अब तक का बेस्ट रिकॉर्ड रहा। सीमा वर्ष 2004 एथेंस में खेलीं, वर्ष 2006 के राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जीता, वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता, वर्ष 2012 के लंदन ओलंपिक में 61.91 का थ्रो करते हुए 13वें स्थान रहीं, वर्ष 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक, वर्ष 2014 में एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक, वर्ष 2018 में एशियन गेम्स में कांस्य पदक और वर्ष 2018 गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक जीता।
- वहीं पहलवान सरिता मोर ने 12 साल की उम्र में चौधरी भरत सिंह मेमोरियल स्पोर्ट्स स्कूल, निडानी में कुश्ती का अभ्यास शुरू किया था। सरिता मोर का जन्म 16 अप्रैल, 1995 को सोनीपत के गाँव बरोदा में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। वह तीन भाई-बहनों में सबसे बड़ी हैं।
- सरिता मोर एक भारतीय फ्री स्टाइल पहलवान हैं। इन्होंने 2017 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 58 किग्रा. भार वर्ग में रजत पदक, 59 किग्रा. भार वर्ग में 2020 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक, 2021 में रोम इटली में आयोजित सीरीज में 57 किग्रा. भार वर्ग स्पर्धा में रजत पदक और हाल ही में विश्व रैंकिंग श्रृंखला 2022 अल्मार्टी (कजाखस्तान) में स्वर्ण पदक जीतकर अपनी श्रेणी (59 किग्रा. भार वर्ग) में विश्व नंबर 1 रैंकिंग तक पहुँचने में कामयाबी हासिल की।

- भारतीय जूनियर कुश्ती टीम के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षक राज सिंह छिक्कारा को कुश्ती के खेल में दिये गए उनके योगदान को देखते हुए ट्रोणाचार्य अवार्ड (लाइफटाइम अवार्ड) दिया जाएगा। राज सिंह छिक्कारा ने देश को करीब 70 अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिये हैं। ओलंपिक मेडलिस्ट योगेश्वर दत्त, एशियन गेम्स मेडलिस्ट मौसम खत्री, परवेश, युद्धवीर, कुलबीर, रविंद्र भूरा, डालमिया, सुनील कुमासपुर, सतपाल, सोनू आदि ने इनके मार्गदर्शन में कुश्ती में देश का नाम चमकाया है।
- उल्लेखनीय है की खेलों में उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिये हर साल राष्ट्रीय खेल पुरस्कार दिये जाते हैं। पिछले चार वर्षों की अवधि में 'खेल-कूद और गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन ए नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन जैसी खूबियाँ दिखाने के लिये अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है।
- ट्रोणाचार्य पुरस्कार खेल-कूद और गेम्स में लगातार उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सक्षम बनाने वाले कोचों को दिया जाता है।

मानेसर में आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का होगा शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

15 नवंबर, 2022 को हरियाणा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाए जाने हेतु मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 21 नवंबर को राज्य के मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करेंगे।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत राज्य के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को भी लाभ देने की शुरुआत की है, जिनका नाम वर्ष 2011 के सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना (एसईसीसी) डाटा में दर्ज नहीं था।
- हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ देने के लिये सरकार द्वारा लगातार स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढीकरण और विस्तारीकरण किया जा रहा है। इसलिये मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन से राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए राज्य में एसईसीसी सूची में शामिल परिवारों के अलावा ऐसे सभी परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपए तक है, उन्हें आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
- एसईसीसी डाटा के अलावा इस योजना में शामिल किये जाने वाले अन्य परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में 'आयुष्मान भारत योजना' की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य देश में जरूरतमंद व वंचितों को स्वास्थ्य सुविधाएँ देना था।
- राज्य में भी एसईसीसी सूची के अनुसार पात्र लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा अधिक-से-अधिक गरीब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मुहैया करवाने के उद्देश्य से बीपीएल परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है।
- ज्ञातव्य है कि केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार हरियाणा में 15,51,798 परिवार इस योजना में कवर हो रहे थे, लेकिन राज्य सरकार ने योजना का दायरा बढ़ाया, जिसके कारण अब राज्य के 28 लाख परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इन सब परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा भी मुहैया करवाई जाएगी।
- हरियाणा में अब तक 28,89,036 आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कुल 715 अस्पताल एम्पैनलड हैं, जिनमें 539 निजी अस्पताल और 176 सरकारी अस्पताल शामिल हैं। इन अस्पतालों के माध्यम से जरूरतमंद व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल रहा है।

हरियाणा के साइबर पुलिस स्टेशन में अब टैक्नोक्रेटस को रखा जाएगा

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने गृह एवं पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य के साइबर पुलिस स्टेशन में अब टैक्नोक्रेटस को रखा जाएगा ताकि साइबर अपराध पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके।

प्रमुख बिंदु

- अनिल विज ने बताया कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक साइबर से संबंधित टैक्नोक्रेट रखने के लिये अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर टैक्नोक्रेटस को रखा जाए। इसके अलावा, आगामी 30 नवंबर तक पुलिस पब्लिक कमेटियों का गठन किया जाएगा, जिसमें कमेटियों में शहर के चुनिंदा व मौजिज, जिसमें विभिन्न संस्थाओं, संगठनों के लोगों को भी शामिल किया जाएगा।
- बैठक के दौरान हरियाणा पुलिस नियमों के संबंध में भी चर्चा की गई और मंत्री को अवगत करवाया गया कि इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया है जो इन नियमों की जाँच पर कार्यवाही कर रही है तथा इन नियमों को आगामी 31 दिसंबर, 2022 तक आगामी कार्यवाही के लिये सरकार को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी।
- बैठक में विज ने कहा कि अंबाला और करनाल रेंज में कार्यरत पुलिस कर्मियों के पदोन्नति के संबंध में जल्द ही निर्णय लिया जाएगा और वरिष्ठता को मदेनजर रखते हुए पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की जाएगी, जिसके लिये आज उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश दिये हैं।
- हरियाणा को अपराध मुक्त व सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में गृह मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के कार्य में तेजी लाई जाए।
- अनिल विज ने बताया कि हरियाणा में अब शस्त्र लाईसेंस के लिये नए स्मार्ट कार्ड जारी किये जाएंगे।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे राज्य के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों व पुलिस आयुक्तों को निर्देश जारी करें कि वे प्रतिदिन सुबह 11 बजे से 12 तक जनता की समस्याओं का निराकरण करें जिससे बहुत से मामलों का निराकरण उनके स्तर पर ही हो जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने पहली बार यूएनएफसीसीसी- सीओपी में की भागीदारी

चर्चा में क्यों ?

16 नवंबर, 2022 को एक सरकारी प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पहली बार विश्व मंच पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) के कांफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) के 27वें सत्र में हिस्सा लिया। यह शिखर सम्मेलन, 6-18 नवंबर 2022 तक मिस्त्र के शर्म अल-शेख में आयोजित हो रहा है।

प्रमुख बिंदु

- हरियाणा के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल इस सम्मेलन में भाग लेने के लिये शर्म-अल-शेख के दौरे पर है।
- मिस्त्र के शर्म-अल-शेख में आयोजित सीओपी-27 में राज्य सरकार की ओर से 'मिशन लाइफ'- लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट - 'पर्यावरण के लिये जीवन शैली'को लागू करने के लिये की जा रही विभिन्न पहलों पर तैयार कार्य योजना को प्रस्तुत किया गया, जिसमें विभिन्न देशों, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिभागियों तथा युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।

- विदित है कि 'मिशन लाइफ'को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा अक्टूबर 2022 में गुजरात में दिया गया था।
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जिनके पास पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन पोर्टफोलियो भी है, के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने पर्यावरण अनुकूलन कई पहल शुरू करने के साथ-साथ प्रदेश में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिये ठोस कदम उठाए हैं। इसके अलावा, वन एवं शिक्षा मंत्री कंवर पाल के नेतृत्व में पौधरोपण और हरियाली अभियान में छात्रों व युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है।
- उल्लेखनीय है कि यूएनएफसीसीसी रियो कन्वेंशन में से एक है और 190 से अधिक सदस्य देश जलवायु परिवर्तन पर विचार करने के लिये चुनौतियों और रोड मैप पर विचार-विमर्श करने के लिये सीओपी-27 में भाग ले रहे हैं।
- प्रवक्ता ने बताया कि सीओपी-27 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यूके के ग्लासगो में सीओपी-26 के दौरान भारत के जलवायु परिवर्तन से संबंधित कार्य योजना और प्रतिबद्धताओं के पाँच अमृत तत्वों (पंचामृत) पर हरियाणा द्वारा दी जा रही पहलों को प्रस्तुत किया गया। विशेष इवेंट में हरियाणा सरकार की उन पहलों को दिखाया गया है, जो जलवायु लक्ष्यों और 2070 तक जलवायु तटस्थता के लिये भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करती हैं।
- हरियाणा ने एग्रोफोरेस्ट्री और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट (टीओएफ) को बढ़ावा देने में बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। वन क्षेत्र के तहत केवल 5 प्रतिशत के साथ वन की कमी वाला राज्य होने के बावजूद, हरियाणा का देश के प्लाईवुड उत्पादन में गैर-वन क्षेत्रों से प्राप्त कृषि आधारित लकड़ी का लगभग 50 प्रतिशत का योगदान है।
- हरियाणा यूएसएआईडी समर्थित टीओएफआई (ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट्स इन इंडिया) कार्यक्रम का भी हिस्सा है, जिसे भारत के सात राज्यों में लागू किया जाना है। टीओएफआई कार्यक्रम 420 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर सीक्वेस्ट्रेशन में योगदान देगा और टीओएफ के तहत 8 मिलियन हेक्टेयर नई भूमि को कवर करेगा।
- सीओपी-27 के दौरान आयोजित विशेष इवेंट में विषयगत क्षेत्रों- जल, वायु, पृथ्वी, जंगल, ऊर्जा और अपशिष्ट से प्रयोग करने योग्य उत्पाद (वेस्ट टू वेल्थ) संरक्षण के लिये प्रक्रियाओं एवं प्रौद्योगिकियों पर अनुसंधान पर केंद्रित छह अंतर्विषयक केंद्रों की स्थापना के माध्यम से जलवायु कार्रवाई का प्रदर्शन किया जा रहा है।

इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 हुई अधिसूचित

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को हरियाणा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी-2022 को अधिसूचित कर दिया है, जिसके तहत 12 योजनाओं को लाइव किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों और उनके घटकों के निर्माण को बढ़ावा देना है। इस पॉलिसी के बनने से इलेक्ट्रिक-व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इसमें आधारभूत संरचना को मजबूत करने के अलावा इलेक्ट्रिक-वाहनों की अग्रिम लागत को कम करने के लिये प्रावधान भी किये गए हैं, जिससे हाइब्रिड ईवी के खरीदारों को प्रोत्साहन भी मिलेगा।
- इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिये जिन 12 योजनाओं को लाइव किया गया है, उनमें खरीदारों के लिये खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, शुद्ध एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, विद्युत शुल्क छूट योजना, स्टाम्प शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, आर एंड डी प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।

हरियाणा पुलिस के 4 अधिकारी 'केंद्रीय गृह मंत्री पदक' से सम्मानित

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को हरियाणा पुलिस विभाग के प्रवक्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हरियाणा के चार पुलिस अधिकारियों को वर्ष-2022 के लिये अन्वेषण में उत्कृष्टता हेतु 'केंद्रीय गृह मंत्री पदक' से अलंकृत किया गया है। अलंकृत होने वालों में एक महिला पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- पुलिस विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इंस्पेक्टर बसंत कुमार, सब इंस्पेक्टर योगेश कुमार, महिला सब इंस्पेक्टर सुमन देवी और हेड कॉन्स्टेबल गोपाल चंद को इस प्रतिष्ठित मेडल से सम्मानित किया गया।
- इस प्रतिष्ठित पदक से अलंकृत पुलिस अधिकारियों द्वारा अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देते हुए साइंटिफिक इन्वेस्टीगेशन के माध्यम से मामलों को सुलझाया गया।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 में इस मेडल की स्थापना अपराध की जाँच के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देने और जाँच अधिकारियों द्वारा इस तरह की 'जाँच में उत्कृष्टता' को मान्यता देने के उद्देश्य से की गई थी।

हरियाणा में बनेगा पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि हरियाणा में पहला इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- संजीव कौशल ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि अन्य स्थानों पर बने इस प्रकार के इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (आईसीसी) का भी बारीकी से अध्ययन किया जाए और उनकी व्यवहार्यता का भी मूल्यांकन किया जाए।
- उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर फरीदाबाद के सेक्टर-78 में बनाया जाना है, इसके निर्माण में तेजी लाने के लिये अगले 15 दिनों में हितधारकों के साथ बैठक का आयोजन किया जाएगा।

प्रदेश भर में स्थापित होंगे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर

चर्चा में क्यों ?

17 नवंबर, 2022 को चंडीगढ़ में आईसीसीसी परियोजना के तहत गठित समिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार हर जिले में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) स्थापित किये जाएंगे।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के मुख्य सचिव ने बताया कि इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) सुरक्षा और निगरानी, यातायात प्रबंधन, टोस अपशिष्ट प्रबंधन और ई-गवर्नेंस एप्लीकेशन के प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ रियल टाइम जानकारी प्राप्त करने में सहयोगी साबित होंगे।
- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार पहले से ही तीन जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद और करनाल में आईसीसीसी के पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं।

- उन्होंने बताया कि आईसीसीसी परियोजना पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए राज्य में अपराध पर अंकुश लगाने में मील का पत्थर साबित होगी। राज्य सरकार इस योजना को लागू करने के लिये अपना मॉडल तैयार करेगी, जो थर्ड पार्टी की निर्भरता को खत्म कर देगा। स्मार्ट सिस्टम को अपडेट करने के लिये परियोजना की हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी।
- उन्होंने बताया कि इस परियोजना घटकों में सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सॉल्यूशन, सेंसर/कैमरा, डिवाइस और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। अगले सप्ताह तक इस प्रोजेक्ट के प्रस्तावित प्रारूप को विस्तृत जानकारी के साथ मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

साइबर सिटी गुरुग्राम की अब होगी अपनी मेट्रो ट्रेन

चर्चा में क्यों ?

18 नवंबर, 2022 को चंडीगढ़ में हुई हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचएमआरटीसी) के निदेशक मंडल की 50वीं बैठक में हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य की साइबर सिटी गुरुग्राम की अब अपनी मेट्रो ट्रेन होगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बताया कि मेट्रो ट्रेन के लिये केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने गुरुग्राम में हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी के बीच 28.5 किलोमीटर लंबी मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी दे दी है। यह पूरे गुरुग्राम शहर को कवर करेगी।
- मुख्य सचिव ने बताया कि यह मेट्रो रेल विशेषरूप से गुरुग्राम और इसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को कुशल तथा पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली प्रदान करेगी। इससे गुरुग्राम और आसपास के छात्रों, महिलाओं, कामकाजी वर्ग एवं कार्यालय जाने वाले व्यक्तियों को काफी मदद मिलेगी।
- उन्होंने बताया कि गुरुग्राम में रेजांगला चौक से सेक्टर-21 द्वारका तक कनेक्टिविटी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा पहले ही अनुमोदित किया जा चुका है और उसके बाद भारत सरकार को भी मंजूरी के लिये भेजा जा रहा है।
- यह मेट्रो रेल गुरुग्राम से दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे तक निर्बाध कनेक्टिविटी भी प्रदान करेगी।
- गौरतलब है कि राजस्व की दिशा में गुरुग्राम मेट्रो ने पिछले वर्ष की तुलना में इस वित्तीय वर्ष में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। पिछले साल की 84 करोड़ रुपए आय की तुलना में अक्टूबर 2022 तक 21.6 करोड़ रुपए की आय हो चुकी है। वित्तीय प्रदर्शन में 230 प्रतिशत की बढ़ी हुई प्रतिशतता के साथ यात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ-साथ वाणिज्यिक गतिविधियों के माध्यम से किराया और गैर-किराया राजस्व से भी आय में वृद्धि हुई है।
- उन्होंने बताया कि इस मेट्रो रेल में सवारियों की संख्या 8500 प्रतिदिन से बढ़कर 40,000 प्रतिदिन हो गई है। इन प्रयासों से पहली बार रैपिड रेल मेट्रो गुरुग्राम, जो घाटे में चल रही संस्था थी, 'ऑपरेशनल प्रॉफिट' में आने वाली है।
- गुरुग्राम एचएमआरटीसी द्वारा अपने मेट्रो स्टेशन क्षेत्रों में नीचे चार्जिंग और पार्किंग की सुविधा देने की भी कवायद की जा रही है जो अंतिम मील तक कनेक्टिविटी में मदद करेगी। जनता की सुविधा और यात्रियों की संख्या बढ़ाने के लिये मेट्रो स्टेशनों से अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

संस्कृत साहित्यकारों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा संस्कृत अकादमी के निदेशक डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के संस्कृत विद्वानों और साहित्यकारों की सम्मान राशि में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है।

प्रमुख बिंदु

- डॉ. दिनेश शास्त्री ने बताया कि सम्मान राशि के अलावा सम्मान की नियमावली में भी फेरबदल किया गया है। सर्वोच्च सम्मान संस्कृत साहित्यालंकार और हरियाणा गौरव के लिये अब आयु सीमा का बंधन हटा दिया गया है। छात्रवृत्ति, अनुदान और वित्तीय सहायता योजना की राशि में भी कई गुना बढ़ोतरी की गई है।

- उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय स्तर के सम्मान 'संस्कृत साहित्यालंकार सम्मान'में 2 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी है। इसी तरह 'हरियाणा संस्कृत गौरव सम्मान'की पुरस्कार राशि दो लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है।
- महर्षि वाल्मीकि और महर्षि वेदव्यास सम्मान की राशि डेढ़ लाख रुपए से बढ़ाकर तीन लाख रुपए कर दी गई है। महर्षि विश्वामित्र सम्मान की राशि डेढ़ लाख से बढ़ाकर ढाई लाख रुपए, आचार्य स्थाणुदत्त सम्मान में अब डेढ़ लाख के स्थान पर दो लाख रुपए मिलेंगे। इसी क्रम में महाकवि बाणभट्ट सम्मान के तहत एक लाख के स्थान पर ढाई लाख रुपए मिलेंगे। साहित्यकार सम्मान राशि पहले 11 लाख थी, जो अब बढ़कर 25 लाख हो गई है।
- निदेशक ने बताया कि आचार्य सम्मान की पुरस्कार राशि चार लाख रुपए से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसी प्रकार, अब गुरु विरजानंद आचार्य सम्मान, विद्यामार्तंड पं. सीताराम शास्त्री आचार्य सम्मान, पं. युधिष्ठिर मीमांसक आचार्य सम्मान को अब एक लाख रुपए से बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है। स्वामी धर्मदेव संस्कृत समाराधक सम्मान के लिये भी अब एक लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर दो लाख रुपए कर दिया गया है।
- संस्कृत की नवलेखन प्रतिभाओं के लिये पुस्तक पुरस्कार राशि को भी 31,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 रुपए कर दिया गया है। इससे साहित्य लेखन में प्रतिभाएँ और उत्साहपूर्वक कार्य करेंगी। पांडुलिपि प्रकाशनार्थ सहायतानुदान के मानदेय की राशि 10,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए कर दी गई है। लघु संस्कृत कथा लेखन, नाटक लेखन प्रतियोगिता में प्रथम को अब 10,000 रुपए द्वितीय को 8,000 रुपए तथा तृतीय को 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। सांत्वना पुरस्कार भी 3,000 रुपए से 6,000 रुपए किये गए हैं।
- डॉ. शास्त्री ने बताया कि संस्कृत पढ़ने वाले छात्रों को भी सरकार ने विशेष तोहफा दिया है। इसके तहत प्रथमा, पूर्व मध्यमा, उत्तर मध्यमा, विशारद, प्राक् शास्त्री और शास्त्री कक्ष में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति राशि अब 3,000 रुपए की जगह 8,000 रुपए मिलेगी। इसके अलावा आचार्य कक्षाओं के छात्रों को 10,000 रुपए मिलेंगे।
- अभावग्रस्त संस्कृत लेखकों को चिकित्सा खर्च के लिये एक वर्ष में 3,000 रुपए की जगह 50,000 रुपए की सहायता मिल सकेगी। इसी तरह लेखक को वित्त वर्ष में मिलने वाली वित्तीय अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 6,000 रुपए से सीधे 21,000 रुपए कर दिया गया है।

हरियाणा ने सुशासन पुरस्कार योजना के शुरू होने की अधिसूचना जारी की

चर्चा में क्यों ?

19 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि राज्य सरकार ने उल्लेखनीय और अभिनव कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिये 'सुशासन पुरस्कार योजना' शुरू की है। इसके लिये अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि 'सुशासन पुरस्कार योजना'का उद्देश्य सुशासन को बढ़ावा देना और उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करना है, जो अपने व्यक्तिगत नवाचारों एवं विशेष प्रयासों के माध्यम से राज्य में सुशासन को बढ़ावा देते हैं।
- उन्होंने बताया कि सुशासन पुरस्कार दो स्तरों पर दिये जाएंगे- एक राज्यस्तरीय पुरस्कार और दूसरा जिलास्तरीय पुरस्कार। राज्यस्तरीय पुरस्कार में व्यक्तिगत कर्मचारियों या कर्मचारियों की विजेता टीम को पहला पुरस्कार 51 हजार रुपए नकद, दूसरा पुरस्कार 31 हजार रुपए और तीसरा पुरस्कार 21 हजार रुपए का दिया जाएगा।
- इसी प्रकार, जिलास्तरीय पुरस्कार में पहला पुरस्कार 31 हजार रुपए नकद, दूसरा पुरस्कार 21 हजार रुपए और तीसरा पुरस्कार 11 हजार रुपए दिया जाएगा। इन पुरस्कार में नकद पुरस्कार के साथ ट्रॉफी, मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित प्रशंसा पत्र (जिसकी प्रति कर्मचारी की सर्विस बुक में लगेगी) भी दिया जाएगा।
- योजना के अनुसार राज्य स्तर पर अधिकतम 10 पुरस्कार दिये जाएंगे। पहले पायदान के लिये 2 पुरस्कार, दूसरे स्थान के लिये 3 पुरस्कार और तीसरे के लिये 5 पुरस्कार दिये जाएंगे। इसी प्रकार, जिला स्तर पर तीनों पायदान के लिये प्रत्येक जिले में 3-3 पुरस्कार दिये जाएंगे।

- उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना, 2022 शुरू की है, जो ग्रुप ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारियों तथा हरियाणा सरकार के अधीन किसी भी विभाग, बोर्ड, निगम, वैधानिक प्राधिकरण, मिशन, सोसायटी, संस्थान, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आदि में आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाले कर्मचारी और व्यक्तियों, जिन्होंने निर्दिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय और अभिनव कार्य किया है, पर लागू है। हालांकि, यह योजना प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों और एआईएस अधिकारियों पर लागू नहीं है।

33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान द्वारा कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खेल प्रांगण में 33वीं राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान कुरुक्षेत्र के प्रिंसिपल नारायण ने बताया कि 23 नवंबर तक चलने वाला यह खेलों का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। एथलेटिक्स की विभिन्न स्पर्धाओं में 728 महिला व पुरुष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
- यह कार्यक्रम लगभग 100 निर्णायकों के मार्गदर्शन में संपन्न होगा। इस टूर्नामेंट से अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, जो भविष्य में देश का नाम रोशन करेंगे। इतना ही नहीं युवा पीढ़ी को एक नई दिशा मिलेगी।
- राज्यपाल ने कहा कि केंद्र सरकार व राज्य की खेल नीति से हरियाणा एक खेल हब के रूप में उभरा है। हरियाणा ने देश की जनसंख्या का मात्र अढ़ाई प्रतिशत होते हुए भी खेलों में भारत का नाम रोशन किया।
- उन्होंने बताया कि राज्य की नई खेल नीति के तहत हरियाणा सरकार ने एक साल में 100 करोड़ रुपए की राशि नकद ईनाम के रूप में खिलाड़ियों को प्रदान की है। इसके साथ-साथ राज्य के बजट में खेलों के लिये 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो किसी भी बड़े राज्य से अधिक है। राज्य में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिये सुरक्षित रोजगार सुनिश्चित करने के लिये नए खेल नियम-2021 बनाए गए हैं।

झज्जर ज़िला के बाढ़सा में 50 एकड़ में खुलेगा आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन कैंपस

चर्चा में क्यों ?

20 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में हरियाणा भवन में आईआईटी दिल्ली के अधिकारियों के साथ बैठक में बताया कि राज्य के झज्जर ज़िला के गाँव बाढ़सा में लगभग 50 एकड़ भूमि पर आईआईटी दिल्ली का एक्सटेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि बाढ़सा में स्थित राष्ट्रीय कैंसर संस्थान से मिलने वाले मरीजों के डाटा और स्वास्थ्य विज्ञान का आईआईटी दिल्ली की टेक्नोलॉजी के समावेश से नई हेल्थ केयर प्रौद्योगिकियाँ विकसित होंगी। इससे मरीजों के साथ-साथ खिलाड़ियों को भी लाभ मिलेगा।
- इस कैंपस में एमएससी, पीएचडी के अलावा विभिन्न प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स भी करवाए जाएंगे। इन विशेष कोर्सें और ट्रेनिंग प्रोग्राम से युवाओं की स्किलिंग होगी तथा स्थानीय युवाओं के लिये विभिन्न प्रकार के रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
- उन्होंने बताया कि यह कैंपस भारत का प्रेसीडेंट मेडिसिन, अर्थात् मरीज विशेष को किस प्रकार की दवा की आवश्यकता है, अनुसंधान से वह दवा विकसित करने का भारत का पहला केंद्र बनेगा। इसके लिये मेडिकल विशेषज्ञों से मरीज की जरूरत का पता लगाकर बायोइंजीनियरिंग के सॉल्यूशन ढूँढे जाएंगे, जिससे फार्मा कंपनियों को लाभ होगा।
- मेडिकल विशेषज्ञ कैंसर मरीजों के लिये राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के चिकित्सा विशेषज्ञों और आईआईटी दिल्ली के तकनीकी विशेषज्ञों की रिसर्च के आधार पर नई दवा विकसित कर पाएंगे, जो मरीजों के इलाज के लिये अनुकूल होगी।

- मुख्यमंत्री ने बताया कि इस कैंपस में खिलाड़ियों को और बेहतर प्रदर्शन करने में मदद देने के लिये स्पोर्ट्स में बेहतर प्रदर्शन और चोटिल होने से बचाने की तकनीक भी विकसित की जाएगी। राज्य के खिलाड़ी पहले ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जब उन्हें तकनीकी मदद मिलेगी तो वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे।
- यह तकनीक पैरालंपिक खिलाड़ियों के लिये बेहद उपयोगी सिद्ध होगी। खिलाड़ियों के लिये विकसित की जाने वाली तकनीक और रिसर्च को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी राई (सोनीपत) के साथ तालमेल करके विकसित करने का सुझाव दिया, ताकि खिलाड़ी उसका ज्यादा लाभ उठा सकें।
- इसके अलावा इस कैंपस में मेडिकल इमेजिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग से कैंसर के मरीजों के इलाज के लिये तकनीक विकसित होगी, जिससे कैंसर के टिशू के उद्गम स्थान का पता लगाया जा सकेगा और उसके बाद शरीर में कैंसर से ग्रस्त पूरे अंग को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर डेंटल इंप्लांट्स, बुजुर्गों में हिप प्रोटेक्शन डिवाइस लगाने, प्रोस्थेटिक घुटने के जॉइंट आदि।

जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कवरेज में अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद अग्रणी घोषित

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्रशासनिक सचिवों की समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए बताया कि भारत सरकार द्वारा जारी जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत हरियाणा के तीन जिलों अंबाला, रोहतक और फरीदाबाद को शत-प्रतिशत नल कनेक्शन कवरेज में अग्रणी घोषित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बैठक में बताया कि जल जीवन सर्वेक्षण 2022-23 के तहत राज्य के तीन जिलों में प्रथम स्थान पर अंबाला, द्वितीय स्थान पर रोहतक व फरीदाबाद जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है।
- बैठक में तकनीकी शिक्षा, बिजली, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी, नागरिक उडन्यन, लोक निर्माण (भवन एवं सड़कें), वास्तुकला, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान, सिंचाई एवं जल संसाधन, सहकारिता और गृह विभाग सहित 10 विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक की 54 परियोजनाओं पर चर्चा की गई। इन 54 परियोजनाओं की कुल लागत लगभग 16 हजार करोड़ रुपए है।
- बैठक में 100 करोड़ रुपए से अधिक की पूरी हो चुकी बड़ी परियोजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत गुरुग्राम में सेक्टर-14, 17, 30, 31, 32, 40, झारसा और डीएलएफ डिवीजन के तहत मौजूदा 11 केवी फीडर लाइन का नवीनीकरण कार्य 255.8 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जा चुका है। इसी प्रकार, 57 करोड़ रुपए की लागत से करनाल-मेरठ रोड, एनएच 709ए की 6 लेन का चौड़ीकरण, 247.25 करोड़ रुपए की लागत से राय मिलकपुर से खड़क कॉरिडोर एवं भिवानी बाईपास तक 4 लेन सड़क का निर्माण, 105.92 करोड़ रुपए की लागत से गुरुग्राम में 576 बहुमंजिला मकानों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है।
- बैठक में बताया गया कि मेवात जिले के झिरका एवं नगीना खंड के 80 गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये जलापूर्ति में वृद्धि हेतु 210.9 करोड़ रुपए की लागत से कार्य किया जा रहा है। इसके अलावा भालखी, महेंद्रगढ़ में 114.7 करोड़ रुपए की लागत से अमल में लाई जा रही जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा होने की कगार पर है।
- उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में योजना बनाकर रिपोर्ट भिजवाने, महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिये अंतर विभागीय समन्वय को मजबूत करने के भी निर्देश दिये।

प्रदेश में 'चिरायु हरियाणा' योजना का शुभारंभ

चर्चा में क्यों ?

21 नवंबर, 2022 को हरियाणा के विकास एवं पंचायत तथा पुरातत्त्व मंत्री देवेन्द्र सिंह बबली ने राज्य के गोहाना तहसील के सेक्टर-7 स्थित सामुदायिक केंद्र में आयोजित आयुष्मान भारत योजना के अंत्योदय परिवारों के विस्तार कार्यक्रम में बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में राज्य में चिरायु हरियाणा योजना की शुरुआत हुई है, जिसके तहत जरूरतमंदों व वंचितों को निःशुल्क बेहतरीन उपचार सुविधा मिल सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- देवेन्द्र सिंह बबली ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विस्तार देते हुए राज्य के जरूरतमंदों को लाभ देने की दिशा में अनुकरणीय कदम बढ़ाए हैं तथा इस योजना को अब 'चिरायु हरियाणा' नाम दिया है।
- इस योजना में शामिल किये जाने वाले इन परिवारों का 5 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि राज्य में अब 28 लाख से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना के विस्तारीकरण से 12 लाख से अधिक नए बीपीएल परिवारों को इसमें जोड़ा गया है।
- विदित है कि राज्य के सोनीपत जिले में पहले 3 लाख 84 हजार पात्र परिवार थे और अब पात्र परिवारों की संख्या बढ़कर 5 लाख 48 हजार 01 हो गई है। यह कुल जनसंख्या का 40 प्रतिशत है।
- उन्होंने बताया कि शुरुआती तौर पर कुछ चिह्नित परिवारों को इस योजना के गोलडन कार्ड वितरित किये गए हैं। शेष पात्र परिवारों को जिला व खंड स्तर पर कैंप लगाकर और घर-घर जाकर कार्ड वितरित किये जाएंगे।

श्री माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को 'होली कॉम्प्लेक्स' बनाया जाएगा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सचिवालय में हुई श्री माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड की बैठक में बताया कि राज्य के पंचकुला स्थित माता मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को 'होली कॉम्प्लेक्स' बनाया जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने बताया कि मनसा देवी मंदिर के निर्धारित क्षेत्र में शराब की दुकानों को बंद किया जाएगा। मंदिर क्षेत्र से करीब 5 किलोमीटर के क्षेत्र में शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा। इसके साथ-साथ मौजूदा समय में जो ठेके वहाँ पर हैं, उन्हें भी कहीं ओर आवंटित किया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि श्री माता मनसा देवी परिसर में बन रहे संस्कृत कॉलेज को श्राइन बोर्ड ही चलाएगा। इस कॉलेज में स्टाफ की नियुक्ति, उनका वेतन व विद्यार्थियों से ली जाने वाली फीस श्राइन बोर्ड द्वारा ही तय की जाएगी। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिये यह एक अनूठी पहल है।
- गौरतलब है कि इस कॉलेज की आधारशिला रखी जा चुकी है। श्राइन बोर्ड ने इसके लिये जमीन मुहैया करवा दी है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा।
- मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर में बन रहे वृद्धाश्रम की इमारत लगभग तैयार हो गई है। इसके संचालन के लिये बोर्ड को जल्द से जल्द कोई प्लान तैयार करने के निर्देश दिये गए हैं, ताकि इसे प्रभावी तरीके से संचालित किया जा सके।
- उन्होंने श्री माता मनसा देवी मंदिर में बनने वाले राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान व संस्कृत गुरुकुल के काम को जल्द से जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिये।

प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा हरियाणा

चर्चा में क्यों ?

24 नवंबर, 2022 को हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चंडीगढ़ में प्राकृतिक खेती पर हुई समीक्षा बैठक में बताया कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और अधिक से अधिक किसानों को इस ओर प्रोत्साहित करने हेतु हरियाणा अब प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करेगा, जिससे इस पद्धति की पूरी प्रक्रिया, समयावधि और परिणामों की विस्तृत जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य सचिव ने बताया कि प्राकृतिक खेती पर वैज्ञानिक रिसर्च पेपर तैयार करने के लिये चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति और रिसर्च निदेशक से बातचीत कर जल्द से जल्द इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाएगा।
- उन्होंने बताया कि प्राकृतिक खेती धीरे-धीरे समय की जरूरत बनती जा रही है। इस पद्धति से कम लागत के साथ किसान जैविक पैदावार बढ़ा सकता है और अपनी आय में भी वृद्धि कर सकता है।
- प्राकृतिक खेती का उद्देश्य रसायन मुक्त कृषि, प्रकृति के अनुरूप जलवायु अनुकूल खेती को बढ़ावा देना और पर्यावरण एवं जलवायु प्रदूषण में कमी लाते हुए इस पद्धति को स्थायी आजीविका के रूप में स्थापित करना है। इसके लिये राज्य सरकार द्वारा किसानों को जागरूक और प्रशिक्षित भी किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राज्य में 2 प्रशिक्षण केंद्रों गुरुकुल (कुरुक्षेत्र) और घरौंडा (करनाल) में प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके अलावा, जल्द ही तीन स्थानों चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (हिसार), हमेटी (जींद) तथा मंगियाणा (सिरसा) में 3 और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का मूल उद्देश्य खान-पान को बदलना है, इसके लिये 'खाद्यान्न ही औषधि' की धारणा को अपनाना होगा। किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिये हर खंड में एक प्रदर्शनी खेत में प्राकृतिक खेती करवाई जाएगी। अब तक 5 जिलों में इस प्रकार के प्रदर्शनी खेत तैयार किये जा चुके हैं।
- बैठक में बताया गया कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये अप्रैल, 2022 में राज्य सरकार ने पोर्टल लॉन्च किया था, जिस पर प्राकृतिक खेती अपनाने के इच्छुक किसान अपना पंजीकरण करवा सकें। अब तक इस पोर्टल पर 2992 किसानों ने अपना पंजीकरण करवाया है। 1201 किसानों ने रबी सीजन के दौरान प्राकृतिक खेती करने के लिये अपनी सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा, 3600 मृदा सैंपल भी एकत्रित किये गए हैं।
- प्राकृतिक खेती के लिये प्रथम चरण में सरकार की ओर से प्रशिक्षण और जागरूकता पर अधिक जोर दिया जा रहा है, ताकि किसान इस पद्धति को अच्छे से समझ सकें। प्राकृतिक खेती के लिये अब तक 405 एटीएम, बीटीएम तथा 119 प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये अब मास्टर ट्रेनर के रूप में अन्य किसानों को प्रशिक्षित करने का काम करेंगे। इसके अलावा 151 युवाओं को भी इस खेती की पद्धति का प्रशिक्षण दिया गया है।
- विदित है कि 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिये देसी गाय की खरीद पर 25 हजार रुपए तक की सब्सिडी व प्राकृतिक खेती के लिये जीवामृत का घोल तैयार करने के लिये चार बड़े ड्रमों के लिये हर किसान को 3 हजार रुपए दिये जा रहे हैं। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है।
- इसके अलावा प्राकृतिक खेती के उत्पादों की पैकिंग सीधे किसान के खेतों से ही हो, ऐसी योजना भी तैयार की गई है, ताकि बाजार में ग्राहकों को इस बात की शंका न रहे कि यह प्राकृतिक खेती का उत्पाद है या नहीं।

राष्ट्रपति ने भगवान श्रीकृष्ण की चौदह विद्याएँ व चौसठ कलाओं पर आधारित सर्वांग-चित्र प्रदर्शनी का किया उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

29 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का शुभारंभ किया तथा महोत्सव के पार्टनर स्टेट मध्य प्रदेश के पैवेलियन में जाकर भगवान श्रीकृष्ण की उज्जैन के संदीपनि ऋषि के आश्रम में ग्रहण की गई शिक्षा-दीक्षा पर आधारित सर्वांग-चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसरोवर के किनारे लगाए गए मध्य प्रदेश पैवेलियन में भगवान श्रीकृष्ण की 14 विद्याओं व 64 कलाओं को स्टाइड्स के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है।
- मध्य प्रदेश पैवेलियन में उज्जैन महाकाल कॉरिडोर के मुख्य प्रवेश द्वार के मॉडल को सांस्कृतिक मंच पर प्रदर्शित किया गया है।
- उल्लेखनीय है कि ऋषि संदीपनि के आश्रम में भगवान श्रीकृष्ण ने अपने भाई बलराम व मित्र सुदामा के साथ 64 दिनों में 14 विद्याओं व 64 कलाओं को सीखा था।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा को दी 3 बड़ी परियोजनाओं की सौगात

चर्चा में क्यों ?

29 नवंबर, 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के कार्यक्रमों की श्रृंखला में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के श्रीमद्भगवद् गीता सदन में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार में हरियाणा सरकार की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का वर्चुअली शुभारंभ व शिलान्यास किया।

प्रमुख बिंदु

- राष्ट्रपति ने अंत्योदय परिवारों के लिये 'निरोगी हरियाणा योजना' का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जाँच मुफ्त की जाएगी। पहले चरण में 1 लाख 80 हजार रुपए से कम आय वाले परिवारों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया जाएगा, जबकि शेष आबादी को बाद के चरणों में कवर किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2022-23 के बजट में घोषणा करते हुए यह विज्ञान पेश किया था कि प्रदेश के सभी नागरिकों की 2 साल में कम-से-कम एक बार व्यापक स्वास्थ्य जाँच मुफ्त की जाए। इसी घोषणा को मूर्तरूप देते हुए 'निरोगी हरियाणा योजना' बनाई गई है।
- नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा जारी अंत्योदय परिवारों के आँकड़ों के अनुसार कुल घरों की संख्या 26,64,257 है और जनसंख्या 1,06,06,475 है। अंत्योदय परिवार को इसके सभी सदस्यों की व्यापक जाँच के लिये एक इकाई के रूप में लिया जाएगा और प्रक्रिया को आसान बनाने के लिये आबादी को 5 अलग-अलग आयु समूहों में वर्गीकृत किया गया है। श्रेणी -1 के तहत 0-6 महीने, श्रेणी-2 में 6-59 महीने, श्रेणी-3 में 5-18 वर्ष, श्रेणी-4 में 18-40 वर्ष और श्रेणी-5 में 40 वर्ष से अधिक आयु वर्ग को रखा गया है।
- आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स पात्र आबादी के प्रत्येक घर का दौरा करेंगी तथा उनका निकटतम स्वास्थ्य सुविधा में जाँच के लिये मार्गदर्शन करेंगी। लाभार्थी की सामान्य शारीरिक जाँच की जाएगी। इसके अलावा, अन्य प्रयोगशाला परीक्षण भी किये जाएंगे।
- स्वास्थ्य जाँच के दौरान डाटा का रिकॉर्ड रखने के लिये एक इन-हाउस एप्लिकेशन विकसित किया जाएगा, जिसका उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सुधार में किया जा सकता है।
- डॉक्टरों की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए और वांछित डाक्टर:रोगी अनुपात प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने हर जिले में एक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल बनाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ने जिला सिरसा में 21 एकड़ भूमि पर बनने वाले मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया। इस पर लगभग 950 करोड़ रुपए की लागत आएगी।

- इस महाविद्यालय की स्थापना से जिला सिरसा व आस-पास के क्षेत्रों को बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान को भी प्रोत्साहन मिलेगा। इस महाविद्यालय में 100 एम.बी.बी.एस. छात्रों का वार्षिक प्रवेश होगा और अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त 539 बिस्तरों का अस्पताल होगा।
- इस परिसर में सेवा ब्लॉक के साथ शिक्षण अस्पताल, परीक्षा ब्लॉक के साथ चिकित्सा महाविद्यालय, गर्ल्स हॉस्टल व गर्ल्स इंटर्न हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल व बॉयज इंटर्न हॉस्टल, जूनियर सीनियर रेजिडेंट छात्रावास, अटोप्सी ब्लॉक, अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा, खेल सुविधा, नर्सिंग, पैरामेडिकल और फिजियोथेरेपी कॉलेज, नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल इत्यादि सुविधाएँ होंगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश में 1835 एम.बी.बी.एस. सीटों, 708 एम.डी/एम.एस. सीटों और 155 डी.एन.बी. डिप्लोमा सीटों के साथ 13 चिकित्सा महाविद्यालय कार्यरत हैं। इनमें से 6 राजकीय, 1 राजकीय सहायता प्राप्त और 6 निजी क्षेत्र के हैं। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुलने से प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें 3 हजार से अधिक हो जाएंगी।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग प्रणाली का शुभारंभ किया। शुभारंभ के साथ ही राष्ट्रपति को पहली टिकट के रूप में नेशनल ई-मोबिलिटी कार्ड की प्रतिकृति भेंट की गई।
- भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ओपन लूप टिकटिंग प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है। प्रारंभिक चरण में 6 डिपो, अर्थात् चंडीगढ़, करनाल, फरीदाबाद, सोनीपत, भिवानी और सिरसा में ई-टिकटिंग प्रणाली लागू होगी। इसी तरह हरियाणा रोडवेज के शेष 18 डिपो में जनवरी 2023 के अंत तक इस परियोजना को पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।
- इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य राजस्व लीकेज को बंद करना है। साथ ही ओपन लूप टिकटिंग के उपयोग को बढ़ावा देना, जिसे बाद में पूरे भारत में यात्रा के अन्य तरीकों के लिये भी उपयोग किया जा सकता है।
- इसके अलावा, छूट पाने वालों की पहचान, फर्जी पास को खत्म करना, रियायत पाने वाले यात्रियों के लिये कागजी बचत, कॉमन मोबिलिटी कार्ड के उपयोग के माध्यम से यात्रियों के लिये बेहतर यात्रा अनुभव प्रदान करना, यात्रियों की संख्या के अनुरूप रूट राशनलाइजेशन तथा बसों, सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि करना शामिल है।

राष्ट्रपति ने किया गीता शिल्प कला उद्यान का उद्घाटन

चर्चा में क्यों ?

29 नवंबर, 2022 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरियाणा के धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र के पुरुषोत्तमपुरा बाग में बनाए गए गीता मूर्ति शिल्प उद्यान का उद्घाटन किया।

प्रमुख बिंदु

- इस उद्यान में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मॉडल, गीता एवं भारतीय संस्कृति के अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाने का प्रयास किया गया है। हरियाणा राज्य के साथ-साथ ओडिशा, तेलंगाना, राजस्थान और असम के 21 शिल्पकारों द्वारा दिन-रात अथक् प्रयास करने के उपरांत 21 मूर्तियों को तैयार किया गया है।
- काले संगमरमर से बनी पाँच से 12 टन वजन वाली ये मूर्तियाँ कलाकारों ने एक ही चट्टान के टुकड़ों को तराश कर तैयार की हैं। सभी मूर्तियाँ महाभारत से संबंधित विषयों को लेकर तैयार की गई हैं। इनमें आजादी का अमृत महोत्सव और गीता को भी दर्शाया गया है।
- इस अतुलनीय कार्य से राज्य में लुप्त होती आधुनिक मूर्तिकला के साथ-साथ राज्य के युवा कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष पहचान मिली है। सदियों तक जिंदा रहने वाली यह आधुनिक अदभुत कला राज्य का गौरव एवं मान-सम्मान बढ़ाने का काम कर रही है।
- गीता शिल्प कला उद्यान में 4 राज्यों के 21 शिल्पकारों ने मूर्तियाँ तैयार की हैं, जिनमें कला एवं सांस्कृतिक अधिकारी (मूर्तिकला) हृदय कौशल, जींद से अमित कुमार, भिवानी से अरुण, असम गोवाहाटी से अरुणधती चौधरी, रोहतक से दिनेश सेवाल, कुरुक्षेत्र से गोल्डी, सिरसा से हरपाल, करनाल से कुलदीप सिंह, कमला नगर रोहतक से महिपाल, चांग हरियाणा से मदन सैनी, जींद से मोनू, मीनाक्षी, राजस्थान से नेमा राम, झज्जर से नरेंद्र, कुरुक्षेत्र से प्रिंस शर्मा, ओडिशा से राकेश पटनायक, रेवाड़ी से राहुल, तेलंगाना से डॉ. स्नेहलता प्रसाद, सोनीपत से स्वीप राज, महारौली दिल्ली से सुशांक कुमार, चंडीगढ़ से विरेंद्र कुमार शामिल हैं।